Educrat IAS
ACADEMY
India's Best Mentorship for Civil Services

Contact Details: 9163228921/8910154148

GENERAL STUDIES

Name of the Candidate	HARSH JALAN		
Email ID		Roll No.	0616288
Mobile No.		Date	21/08/23

INDEX TABLE		
Q.No	Max.Marks	Marks Obtained
1	100	00
2	12	06
3	12	03
4	12	05
5	12	05
6	12	05
7	9	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total Marks		24.

INSTRUCTIONS

1. Please write your Name, Email, UPSC Roll No. and Mobile number in the answer sheet
2. There are 20 questions printed in English, all questions are compulsory
3. The number of marks carried by a question or part is indicated against it.
4. Answers must be written in the medium authorized in the admission Certificate (English), which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided.
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be struck off.

Any specific message from Educrat IAS Mentors/Evaluators with respect to your copy?
Mentor's Remarks:

....

....

....

....

....

....

....

....

Start Time: 9 800	End Time: 10 830
Mode of Examination:	Online ☐ Offline ☐
TEST CODE:	Medium of Examination:

नवीकरणीय ऊर्जा - संभावनाएं और चुनौतियाँ

-> Demographic Dividend.

संभावनाएं -> i) 5 trillion Dollar Economy.

ii) Global Leader - in everything

iii) Global Hub of Culture & Information

iv) Doubling Farmers Income

चुनौतिया -> i) Unemployment

ii) Poverty

iii) Healthcare

iv) Intolerance due to Idleness

Educrat IAS ACADEMY India's Best Mentorship for Civil Services

1. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 600 शब्दों में निबंध लिखिए : 100

(a) नवीकरणीय ऊर्जा : संभावनाएँ और चुनौतियाँ

(b) संचार क्रान्ति का महत्त्व

(c) खेलों का बढ़ता व्यवसायीकरण

(d) खान-पान का स्वास्थ्य पर प्रभाव

Renewable Energy

Ans. नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम 'Demographic Dividend' के नाम से भी जानते है का अर्थ है - नवयुवकों की संख्या जो देश का भार सहने के लिए कार्य कर सके देश को उजाला और ऊर्जा बनाने के लिए (15-64) के बीच में।

2023 में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा 62% पे है और ऐसा मानना है कि 2030 में यह आंकड़ा 68% हो जाएगा, जिससे यह मालूम होता है कि भारत के पास केवल कुछ (10-15) साल ही है इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए, और वह उठाने पर इसकी दिक्कतों को झेलने के लिए

नवीकरणीय ऊर्जा अपने साथ ~~कि~~ अवसर और दुविधाएं दोनों लेकर आया है, चलिए हम साथ में कुछ अवसरों और चुनौतियों को देखें.

भारत मे आज करीब एक सौ चालीस करोड़ की आबादी है, अन एमप्लॉयमेंट - 8% के करीब, गरीबी - सोलह करोड़ लोग और ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी मे उपलब्ध है जो बीस परसेंट से भी कम योगदान करते हैं देश के GDP में।

यह जानना बहुत जरूरी है की आखिर जड़ क्या है दिक्कतों की, जिससे उन्हें समाधान कर हम आगे बढ़ सकते है, देश में लोगों की संख्या बहुत है, पर सुविधाएं सिर्फ कुछ लोगों को ही

मिल पाती है जैसे पढ़ने लिखने का अवसर, कार्य करने का, खाना-पानी, रहने के लिए पक्का घर, एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के 10% लोग भारत के 77% संपत्ति समेट के रखे है।

हमें एकदम नीचे से शुरूआत करनी पड़ेगी, माने एकदम गाँव के अंदर से, बिना लड़का-लड़की में भेद-भाव किए। हमें सरवा शिक्षा अभियान संपूर्ण रूप से प्राप्ति करने के लिए व्यवस्थाए लेनी पड़ेगी, हमी बच्चों के मा-बाप को समझाना पड़ेगा शिक्षा का मूल्य और सुविधाए देनी पड़ेगी।

शिक्षा के बाद हमी नवयुको को कार्य करने का अवसर देना होगा जिससे वे अपनी शिक्षा का इस्तेमाल सही से कर सके।

हमे यह करते हुए SC, ST, OBC, LGBT लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा और इन्हे भी संसार से जोड़े रखना होगा। इनके बीच जाकर इनकी दिक्कतों को समझना होगा, ये भी अगर वर्कफोर्स मे आजाए तो अपने साथ कुशलतेनी सीख और नीतिए लेकर आयों को सोचने समझने का एक नया तरीका मिलेगा।

भारत मे सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी मे है, इसके 'Doubling Farmers Income' को एक सच बनाना पड़ेगा, बिना भेद भाव किए होनो जातियों को एक सामान भड़ने का अवसर देना होगा।

यह करने से क्या होगा कि, हम नीचे से सुधार लेकर आएगो, लोगो को शिक्षा, काम करने का अवसर और पैसा कमाने का मौका मिलेगा जिससे उनकी

आर्थिक स्थिति सुधरेगी। फिर वे कारोबार में भी आजाएगो और सरकार का टैक्स कमाई भआएगो। वह पैसा सरकार चारो तरफ से निमार्ण मे इस्तेमाल कर सकती है - नए स्कूल, नये रोड - बिजली की सुविधाए, आदि पर खर्च कर सकती है।

अगर एसा किया जाता है तो एक गोल चक्र बन जाएगा निर्माण का जैसा देश वासी सावधानी कर रहे देश की वजानी मे यात - यात, अगर सरकार यह नही करवा पाती है तो इसका परिणाम भयंकर होगा।

देश मे गरीबी, भुखमरी, लोगो के बीच गुस्सा सरकार के प्रति, देश के सुविधाओ पर बिजलि - राशन, अस्पताल की सुविधाए सब पर बीत पड़ेगा

और क्योंकि सरकार के पास आमदनी ही नहीं रहेगी, वह कुछ कर नहीं पाएगी सफलतापूर्वक जिसके कारण देश में लाव & ऑर्डर भी स्थित और खराब हो जाएगी।

नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ लेने के लिए सरकार को गाँव को शहर बनाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत का चेहरा भले ही इसके शहर हो पर इसका दिल आज भी गाँव में ही बसता है। गाँव से सुधार जब शहर में आएगा तो देश की सोच पे चार चाँद लगा जाएगा क्योंकि यह शहर-गाँव में बटा हुआ देश फिर एक हो जाएगा।

2. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। 12×5=60

औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आँकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नज़र रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, सांख्यिकीय आँकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्टें प्रकाशित करते थे।

प्रारम्भिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर ख़ास ध्यान दिया। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे ज़रूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मज़बूत करने के लिए भी नक्शे बनाये जाने लगे। शहरों के नक्शों से हमें उस स्थान पर पहाड़ियों, नदियों व हरियाली का पता चलता है। ये सारी चीज़ें रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती हैं। इसके अलावा घाटों की जगह, मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान (टैक्स व्यवस्था) की रणनीति बनाने में मदद मिलती है।

उन्नीसवीं सदी के आखिर से अंग्रेज़ों ने वार्षिक नगरपालिका कर वसूली के ज़रिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। टकरावों से बचने के लिए उन्होंने कुछ ज़िम्मेदारियाँ निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी हुई थीं। आंशिक लोक-प्रतिनिधित्व से लैस नगरनिगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ, नगरनिगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए जिन्हें नगरपालिका रिकॉर्ड रूप में सँभालकर रखा जाने लगा।

शहरों के फैलाव पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। इसके बाद, 1881 से दशकीय (हर 10 साल में होने वाली) जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आँकड़े एक बहुमूल्य स्रोत हैं।

जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। बीमारियों से होने वाली मौतों की सारणियों का अन्तहीन सिलसिला, या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है जिससे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने पाया है कि ये आँकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। इन आँकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आँकड़े किसने इकट्ठा किए हैं, और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को मापा गया था और किस चीज़ को नहीं मापा गया था।

(a) औपनिवेशिक शासन चलाने में आँकड़ों का क्या महत्त्व था?

(b) औपनिवेशिक शासकों के लिए मानचित्र क्यों महत्त्वपूर्ण थे?

(c) औपनिवेशिक अभिलेखों के माध्यम से शहरीकरण का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है?

(d) इतिहासकार आँकड़ों को सदैव अहानिकर क्यों नहीं मानते?

(e) औपनिवेशिक शासकों की करों से संबंधित नीति क्या थी?

(a) औपनिवेशिक सासन चलाने के लिए आँकडो का महत्व यह है कि वे व्यावसायिक मामलों को चलाने मे सहायता और जानकारियों को हासिल करने मे साहयता करते है। बढ़ते शहरो मे जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित है और सर्वेक्षण है. साख्यिकीय आँकडे इकट्ठा करने से और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकते है।

(b) प्रारम्भिक वर्षों से औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पे खास ध्यान दिया है क्योंकि सरकार का यह मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य समझना आवश्यक है उस इलाके पर ज्यादा बेहतर नियंत्रण कायम करने के लिए ?

(c) औपनिवेशिक अभिलेखों के माध्यम से शहरीकरण का अध्ययन इस प्रकार किया जा सकता है - वे विकास की योजना और सत्ता मजबूत करने मे सहायता करते हैं, नक्शों को बनाने मे - जिससे शहरी के स्थान पर मौजूद पहाड़ियाँ, नदियाँ और हरियाली का पता चल जाता है। वे रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना बनाने मे मदद करते हैं इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने मे और कारोबार की रणनीति बनाने मे मदद करते हैं।

(d) इतिहासकार आंकड़ों को सटीक अहानिकर इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे गलत भी हो सकते हैं। पूरी तरह विश्वास करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि वे आँकड़े किसने इकट्ठा किए हैं, और इन्हे क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था, किन चीजों को मापा गया था और किनको नहीं, जिससे हम कोई गलत फैसला ना लेंगे।

(e) औपनिवेशिक शासकों की करों से संबंधित नीति यह थी वे नगरपालिका के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने लगे शहरों के देखरेख के लिए। उन्होंने कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी टकरारों से बचने के लिए और नगरनिगम जैसे सेवाएं की उपलब्धी का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी सड़क का निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी सेवाए उपलब्ध कराई। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए जनगणना करवाई, पहला जनगणना 1872 में किया गया, इसके बाद 1881 में दशकीय जनगणना के लिए नियमित व्यवस्था बनाई।